

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 21, बुधवार, शके 1945-जुलाई 12, 2023 Asadha 21, Wednesday, Saka 1945- July 12, 2023	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
अधिसूचना

जयपुर, जून 20, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

संख्या :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के निर्देशानुसार Consultancy Services for preparation of Detailed Project Report (DPR) including Land Acquisition for Construction of Nagla Mana Road in Panchayat Samiti Sewar, District Bharatpur (Length-1.60km) हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील भरतपुर जिला भरतपुर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

विवरण

नंगला माना सड़क निर्माण परियोजना हेतु अवाप्ति की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) कर कार्यवाही

बाबत प्रस्ताव जिला भरतपुर

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	भरतपुर	भरतपुर	सेवर	1 सहनावली 2 नगला माना	उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भरतपुर जिला भरतपुर द्वारा

सलाहकार ए आर इंटरनेशनल कन्सलटेन्सी श्री रोशन कुमावत-सामाजिक विशेषज्ञ 69 नालन्दा विहार महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर 302018 मोबाईल 9414876990 एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगा:

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 4 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सांनिविण खण्ड भरतपुर
जिला भरतपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

ए आर इंटरनेशनल कन्सलटेन्सी

(श्री रोशन कुमावत-सामाजिक विशेषज्ञ)

मोबाईल: 9414876990

69 नालन्दा विहार, महारानी फार्म,

दुर्गापुरा, जयपुर-302018

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।